न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी के समक्ष

शकुंतला देवी, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

शाम नाथ और प्रेम नाथ, — *उत्तरदाता*

सिविल पुनरीक्षण सं. 2702 *सन्* 1985

नवंबर 20, 1986

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) — आदेश VIII, नियम 1, आदेश XXXIII, नियम 2 और 8 — प्रतिवादियों पर निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए वादी का आवेदन दाखिल करना — आदेश XXXIII, नियम 2 के तहत इस तरह के आवेदन में सभी विवरण शामिल होना आवश्यक है वाद-विवाद के संबंध में निर्धारित — प्रतिवादी उस पर उत्तर दाखिल कर रहे हैं — उक्त आवेदन बाद में वापस ले लिया गया लेकिन एक मुकदमे के रूप में माना जाने का आदेश दिया गया — प्रतिवादी वाद-पत्र के उत्तर में लिखित बयान दाखिल करने की मांग कर रहे हैं — आवेदन का उत्तर — क्या आवेदन को वादपत्र के रूप में मानने का आदेश दिए जाने के बाद प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल करने में वर्जित है — एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन — क्या इसे एक समग्र दस्तावेज के रूप में भी माना जा सकता है — लिखित बयान दाखिल करने का अवसर — कब उठता ह।

अभिनिर्णित, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII, नियम 1, जो लिखित बयान दाखिल करने से संबंधित है, में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी 'सुनवाई की पहली तारीख को या उससे पहले' लिखित बयान दाखिल करेगा। आदेश XXXIII, संहिता का नियम 2 इस आशय का है कि एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन में वादों में वाद-विवाद के संबंध में निर्धारित सभी विवरण भी शामिल होने चाहिए और नियम 8 यह निर्धारित करता है कि जब मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन किया जाता है एक निर्धन व्यक्ति को अनुमति दी जाती है, इसे क्रमांकित किया जाएगा और पंजीकृत किया जाएगा और मुकदमे में एक वाद माना जाएगा। सुनवाई की पहली तारीख स्पष्ट रूप से ऐसी छुट्टी दिए जाने के बाद की तारीख होगी और यह प्रतिवादी के लिए लिखित बयान दाखिल करने का अवसर होगा, पहले नहीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आवेदन का उत्तर एक लिखित बयान माना जाएगा जब ऐसा आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। आदेश XXXIII के तहत आवेदन का जवाब दाखिल करना प्रतिवादियों को बाद में आवेदन को एक वाद समझे जाने के बाद उस पर लिखित बयान दाखिल करने से नहीं रोक सकता है। कानून की ऐसी स्थिति होने के कारण,

इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए एक आवेदन को एक समग्र दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार केवल तभी एक वाद माना जा सकता है जब आवेदन स्वीकृत हो या जब न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाता है और इसे एक वादपत्र के रूप में मानने का आदेश दिया जाता है और उसके बाद ही लिखित बयान दाखिल करने का अवसर आता है।

(पैरा 6, 7 और 8)

मुंशीवर पूरी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए ।

अमरजीत मार्कन, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी।

(1) क्या एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के आदेश 33 के तहत एक आवेदन का उत्तर दाखिल करना, प्रतिवादी को आवेदन के समय लिखित बयान दाखिल करने से रोकता है जब आवेदन को वादपत्र माना जाता है? यहीं वाद का मुद्दा है.

(2) एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए, 24 जुलाई, 1981 को शकुंतला देवी ने संहिता के आदेश 33 के तहत प्रतिवादियों पर 23,000/- रुपये की राशि वसूलने के लिए एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। इसके तुरंत बाद शकुंतला देवी की मृत्यु हो गई और बाद में उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया। 3 अप्रैल, 1982 को, प्रतिवादियों ने शकुंतला देवी के आवेदन का जवाब दाखिल किया और इसे एक लिखित बयान बताया, जिससे इसमें निहित सभी आरोपों का खंडन हुआ। इस आवेदन को बाद में 1 मार्च, 1985 के विचारण न्यायालय के आदेश द्वारा वापस लेने की अनुमति दी गई और इसे मुकदमे के रूप में मानने का आदेश दिया गया और मामले को लिखित बयान दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल, 1985 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और फिर 17 मई, 1985 तक किस तारीख को वादी पक्ष ने प्रतिवादियों द्वारा 3 अप्रैल, 1982 को दायर किए गए "लिखित बयान" की प्रतिकृति दाखिल की थी। जबकि प्रतिवादियों ने लिखित बयान दाखिल करने के लिए उन्हें समय दिए जाने के लिए एक आवेदन दायर किया था। इसे इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया गया कि लिखित बयान पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसके बाद मुद्दे तय किये गये। हालाँकि, बाद में, उसी दिन, अर्थात् 17 मई, 1985 को, समीक्षा के लिए एक आवेदन दिया गया जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रतिवादियों को एक लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति दी जाए। वादी पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु विचारण न्यायालय ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा की और प्रतिवादियों को इस आधार पर एक लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी कि संहिता के आदेश 33 के तहत आवेदन को एक वाद में परिवर्तित करने के बाद कोई लिखित बयान

दायर नहीं किया गया था। यह वह आदेश है जिसे अब पुनरीक्षण में चुनौती देने की मांग की गई है।

(3) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा संहिता के आदेश 33 नियम 2 के प्रावधानों पर बहुत बल दिया गया था कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन में वादों के संबंध में निर्धारित सभी विवरण भी शामिल होने चाहिए। तर्क यह है कि जब ये विवरण आवेदन में दिए गए हैं और उस पर एक उत्तर दायर किया गया है, और आवेदन को तर्क की समानता पर एक वाद माना जाने का आदेश दिया गया है, तो इसके उत्तर को भी वादपत्र का लिखित बयान माना जाना चाहिए। इसके अलावा, इसके आवश्यक परिणाम के रूप में, संहिता के आदेश 33 के तहत आवेदन को एक समग्र माना जाना चाहिए, अर्थात्, एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के लिए एक आवेदन और एक वाद भी। ऊपरी तौर पर यह तर्क वास्तव में आकर्षक है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसे कायम रखा जा सके।

(4) संहिता के आदेश 33 के तहत एक आवेदन को एक समग्र दस्तावेज मानने से, यानी एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए एक आवेदन और एक वाद दोनों को संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के विपरीत असंगत परिणाम मिलेंगे जैसा कि था फुल बेंच द्वारा बहुत अच्छी तरह से *चुन्ना मल बनाम भगवंत किशोर* (1) में प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में, सबसे पहले, संहिता के आदेश 33 के नियम 15 के प्रावधानों को बढ़ावा देना उचित होगा, जो एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन को अस्वीकार करने से संबंधित है। इसके संदर्भ में, ऐसा आदेश मुकदमा करने के समान अधिकार के संबंध में समान प्रकृति के किसी भी बाद के आवेदन पर रोक लगाता है, लेकिन यह आवेदक को ऐसे अधिकार के संबंध में सामान्य तरीके से मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाता है, बशर्ते कि वह पहले लागत का भुगतान करे, यदि कोई हो। एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उसके आवेदन का विरोध करने पर राज्य सरकार या विपरीत पक्ष द्वारा खर्च किया गया। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि ऐसी लागतों का भुगतान मुकदमे की स्थापना के लिए एक शर्त है, हालांकि न्यायालय के पास वादी को ऐसी लागतों का भुगतान करने की अनुमति देने का विवेकाधिकार है, क्योंकि वह अनुमति दे सकता है। वादी के बिना दायर किया गया मुकदमा यदि ऐसी लागतों का भुगतान किया जाता है, तो यह कायम रखने योग्य नहीं होगी और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान बाद में लागतों के भुगतान से इस दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है। यहां, यदि एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को एक समग्र के रूप में माना जाता है, तो संहिता के आदेश 33 के नियम 15 के प्रावधानों से सीधे तौर पर वादी द्वारा अपने दावे पर मुकदमा चलाने में सक्षम होने से बचा जा सकता है, पहली बार में, उस नियम में निर्दिष्ट लागत का भुगतान किए बिना।

(1) A.I.R. 1936 Allahabad 584.

(5) इसके अलावा, संहिता का आदेश 33 नियम 5 न्यायालय को एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए एक आवेदन को उन आधारों से काफी अलग और अलग आधार पर खारिज करने की अनुमति देता है जिन पर संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक वाद को खारिज किया जा सकता है।

(6) यहां यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि संहिता के आदेश 8 नियम 1, जो लिखित बयान दाखिल करने से संबंधित है, विशेष रूप से उल्लेख करता है कि प्रतिवादी सुनवाई की पहली तारीख पर या उससे पहले एक लिखित बयान दाखिल करेगा। आदेश 33 संहिता के नियम 8 में प्रावधान है कि जब एक निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आवेदन स्वीकृत किया जाता है, तो इसे क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा और इसे मुकदमे में एक वाद माना जाएगा। सुनवाई की पहली तारीख स्पष्ट रूप से उसके बाद की तारीख होगी ऐसी छुट्टी का अनुदान और इस प्रकार यह प्रतिवादी के लिए लिखित बयान दर्ज करने का अवसर होगा, न कि पहले।

(7) अंततः, यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता में इस आशय का कोई प्रावधान नहीं है कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए आवेदन का उत्तर एक लिखित बयान माना जाएगा, जब ऐसा आवेदन स्वीकृत हो।

(8) कानून की ऐसी स्थिति होने के कारण, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि एक गरीब व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए एक आवेदन को एक समग्र दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार इसे केवल तभी एक वाद माना जा सकता है जब आवेदन दी जाती है या वर्तमान मामले की तरह जब अदालत-शुल्क का भुगतान किया जाता है और इसे एक वादपत्र के रूप में मानने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद ही लिखित बयान दाखिल करने का अवसर आता है। ऐसा होने पर, इस तरह के आवेदन का उत्तर दाखिल करने को प्रतिवादियों को बाद में आवेदन पर लिखित बयान दाखिल करने से रोकने के लिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे एक वाद माना जाता है।

(9) इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से आधे-अधूरे मन से यह तर्क देने का प्रयास किया गया कि अदालत ने प्रतिवादियों को पहले इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद एक लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति देकर अपने पहले के आदेश, दिनांक 17 मई, 1985 की समीक्षा की अनुमति देने में महत्वपूर्ण अनियमितता बरती है। वास्तव में इस संबंध में आक्षेपित आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। संहिता के आदेश 47 नियम 1 के तहत समीक्षा का दायरा स्पष्ट रूप से इतना व्यापक है कि विचारण न्यायालय को लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति न देने की अपनी पिछली त्रुटि को सुधारने की अनुमति मिल गई है।

(10) इसलिए, विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जिसे तदनुसार बरकरार रखा गया है और इसकी पुष्टि की गई है। अत: यह

पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा